

वनमण्डलाधिकारी,  
(सामान्य) वन मंडल मंदसौर, मध्यप्रदेश।

**विषय:-** मंदसौर जिले में गांधीसागर अभ्यारण्य के अन्तर्गत गांधीसागर हेडल-बॉर्डर (रतनगढ़) मार्ग के किनारे-किनारे ओ0एफ0सी0 लाईन डालने हेतु 0.20 हेक्टेयर वनभूमि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, भोपाल को उपयोग पर देने बाबत। (प्र0 क्रमांक/FP/MP/OFC/156036/2022)

**संदर्भ:-** अ.प्र. मुख्य वनसंरक्षक, उज्जैन का पत्र क्र./मा.चि./2022/6172 दिनांक 08.09.2022

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन ने विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

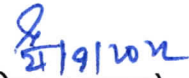
उपरोक्त प्रस्ताव मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 22.08.2022 के अनुसार ROW में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन, पानी की पाईप लाईन, विद्युत लाईन तथा गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति के अधिकार नोडल अधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा दिए निर्देशानुसार प्रकरण में मंदसौर वन मण्डल के परिक्षेत्र गेमरेंज पश्चिम के कक्ष क्रमांक RF-995, 996 में मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- उपरोक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन की चौड़ाई 01 मीटर से अधिक एवं गहराई 02 मीटर से अधिक न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। यह लाईन सड़क के किनारे-किनारे ही डाली जावे।
- 2- प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा जारी की गई वन्यप्राणी अनुमति दिनांक 25.05.2022 में अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 4- NPV: Net Present Value(NPV) amount of Rs. 9,57,780/- is to be paid for the 0.20 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 5- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

- 6- User agency shall restrict the no felling of trees.
- 7- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 8- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 9- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 10- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 11- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 12- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 13- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 14- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि 9,57,780/- आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से वेबपोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी न की जावे।



(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)

मध्य प्रदेश, भोपाल

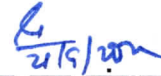
पृ. क्रमांक/एफ-5/1175/2022/10-11/3254  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21/09/2022

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।

2- SCO, Jio Digital Fiber Pvt. Ltd., 3rd Floor, DB Mall, Zone-1 M.P. Nagar Bhopal, Madhya Pradesh.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)

मध्य प्रदेश, भोपाल